भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3639

उत्तर देने की तारीख 02 अप्रैल, 2025

बुधवार, 12 चैत्र 1947 (शक)

पंजाब को केंद्रीय सहायता

3639. श्री हरभजन सिंह:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को राज्य के युवाओं के कौशल को निखारने के लिए पंजाब सरकार की पहलों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कौशल विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पंजाब को वित्तीय सहायता सहित सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पंजाब सरकार ने राज्य के युवाओं को और कुशल बनाने के लिए विभिन्न पहलों की सूचना दी है, जिनका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): भारत सरकार के कुशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार

प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), पंजाब राज्य सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना और उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करना है।

एमएसडीई की योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

	पीएमकेजवीवाई (प्रारंभ से दिनांक 31.12.2024 तक)	जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक)	एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025 तक)	सीटीएस (आईटीआई) (वर्ष 2018-19 सत्र से वर्ष 2023-24 तक)
अखिल भारत	1,60,33,081	28,51,573	35,42,442	79,57,128
पंजाब	5,45,446	19,313	63,496	2,53,243

पीएमकेवीवाई और जेएसएस योजनाओं के अंतर्गत, निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है। जेएसएस योजना के तहत, गैर-सरकारी संगठनों को सीधे निधि जारी की जाती है। एनएपीएस के तहत, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपए तक का वृत्तिका जारी किया जाता है। आईटीआई के संबंध में दैनन्दिन के प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र अभिशासन के पास होता है।

विगत पांच वर्षों (2023-24 तक) के दौरान पंजाब राज्य में पीएमकेवीवाई, जेएसएस और एनएपीएस के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

	करोड़ रुपए में
पीएमकेवीवाई	134.39
जेएसएस	52.93
एनएपीएस	4.56

इसके अलावा, आजीविका संवर्धन कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) के अंतर्गत, एमएसडीई ने राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी), आकांक्षात्मक कौशल अभियान (एएसए) और विशेष परियोजना के तहत पंजाब राज्य को 11.62 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

अनुबंध

'पंजाब को केंद्रीय सहायता' के संबंध में दिनांक 02.04.2025 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3639 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य के युवाओं को और कुशल बनाने के लिए पंजाब सरकार की पहल

(i) औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार, अप्रचलित पाठ्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया गया है और उन्हें संग्रहित किया गया है।

(ii) वर्ष 2024-25 सत्र के दौरान, 137 सरकारी आईटीआई में 32827 शिक्षुओं को प्रवेश दिया गया है। वर्ष 2024-25 सत्र के दौरान, 5000 नई सीटें शुरू की गई हैं।

(iii) वर्ष 2024-25 सत्र में, दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) के तहत 212 इकाइयां कार्यात्मक हैं और लगभग 4518 उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं।

(iv) सरकारी आईटीआई लुधियाना के उन्नयन के लिए, एमपीलैड योजना के तहत लगभग 2.00 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

(v) पंजाब सरकार ने सरकारी आईटीआई के उन्नयन के लिए 50.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

(vi) बजट वर्ष 2025-26 में 25 नए सरकारी आईटीआई के लिए 33.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(vii) इंजीनियरिंग में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए, सरकारी आईटीआई (डब्ल्यू) कपूरथला में इलेक्ट्रीशियन और राजकीय आईटीआई (डब्ल्यू) मोहाली में मैकेनिक डीजल इंजन जैसे पाठ्यक्रम उद्योग के सहयोग से शुरू किए गए हैं।

(viii) राज्य में आईटीआई को और सुदृढ़ तथा उन्नत करने के लिए, पंजाब सरकार ने सीएसआर पहल के तहत डाइकन इंडिया, अशोक लीलैंड, मारुति सुजुकी और आईटीसी लिमिटेड जैसे उद्योगपतियों से निवेश आकर्षित किया है।

(ix) एनएसक्यूएफ को वर्ष 2014-15 में 06 ट्रेडों से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 20 ट्रेडों तक कर दिया गया है, जिसमें 1490 स्कूल और 2624 व्यावसायिक प्रयोगशालाएं शामिल होंगी।

****